नईदुनिया

अहम खनिज दौड़ में भारतीय निजी क्षेत्र का नया दांव, अफ्रीका में बना रहे ठिकाने

नई दिल्ली

भारत अपनी विनिर्माण महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक दौड़ में शामिल है। इसी बीच, कुछ भारतीय मूल के निजी खनिज कारोबारी चुपचाप अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी खनिज संपत्तियां विकसित कर रहे हैं। ये कारोबारी, सार्वजनिक उपक्रमों की सरकारी मदद से अधिग्रहण की रणनीति से हटकर, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।

और अपनी प्राथमिकता भारतीय विनिर्माताओं को खनिज उपलब्ध कराना बता रहे हैं। वे भारत सरकार से वित्तीय सहायता के बजाय चीन की तर्ज पर मजबूत संस्थागत सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश निजी स्वामित्व वाली मध्यम आकार की कंपनियां हैं, जिन्होंने कान्गो, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लीथियम, टिन, टैंटलम, टंगस्टन जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की खानें तैयार कर ली हैं।

ये कंपनियां ग्रेफाइट व कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खानें कर रही हैं विकसित

उद्योग विशेषज्ञों और कंपनी अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों की पहली प्राथमिकता भारतीय विनिर्माताओं को ही खनिज उपलब्ध कराना है। हालांकि, वे चाहते हैं कि जिस तरह चीन ने दशकों से अपनी खनिज कंपनियों को समर्थन दिया है, भारत सरकार भी उनके साथ मिलकर काम करे। उनका मानना है कि ऐसे संस्थागत सहयोग से वे अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन और आपूर्ति कर पाएंगे तथा मेजबान देशों की सरकारों के साथ बेहतर ढंग से निपट सकेंगे। वे वित्तीय सहायता के बजाय दीर्घकालिक वाणिज्यिक संबंधों और सरकार से मजबूत संस्थागत समर्थन की आकांक्षा रखते हैं। इस पहल का एक उल्लेखनीय उदाहरण अहमदाबाद की सकारिया माइंस ऐंड मिनरल्स है, जो तंजानिया में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार (लगभग 18.3 करोड़ टन) विकसित कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार, पहले चरण के विकास में 15 से 20 करोड़ डालर का निवेश होगा और लक्ष्य 40 लाख टन प्रसंस्करण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता भारत होगी। कई बैटरी विनिर्माता भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। अगर हमें सही अवसर मिलता है तो हम पहले भारतीय कंपनियों को आपूर्ति करना चाहेंगे उन्होंने चीन के माडल पर जोर दिया, जहां खनन को मुख्य उत्पाद निर्माण और सतत राज्य समर्थन के साथ एकीकृत किया जाता है, जो केवल विदेशी खदानों के मालिक होने से कहीं अधिक है। भारत की ग्रेफाइट मांग बैटरी निर्माण के साथ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, और इन निजी खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

न्यूज़ ब्रीफ

भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाएगा आस्ट्रेलिया, निजी क्षेत्र पर विशेष ज़ोर

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया भारत के तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन, छोटे उपग्रह निर्माण और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में भागीदारी करना है। आस्ट्रेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के साथ तीन से पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। आस्ट्रेड के व्यापार एवं निवेश आयुक्त नाथन डेविस ने कहा कि आस्ट्रेलिया पृथ्वी अवलोकन, छोटे उपग्रहों के निर्माण व प्रक्षेपण सेवाओं, ट्रैकिंग और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के साथ मिलकर काम करना चाहता है। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स में माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान भी एक संभावित क्षेत्र है। अगले सप्ताह बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में आस्ट्रेलिया प्रौद्योगिकी देश भागीदार के रूप में भाग लेगा, जिसमें नौ कंपनियों और तीन विश्वविद्यालयों सहित 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। सिडनी स्थित स्पेस मशीन्स और लैटकनेक्ट 60 जैसी कंपनियां पहले ही भारतीय स्टार्टअप के साथ साझेदारी कर चुकी हैं, जबकि रिसर्चसैट जैसी कंपनियां भारत में भागीदार तलाश रही हैं। आस्ट्रेलिया का अंतरिक्ष क्षेत्र वर्तमान में 4.6 अरब का वार्षिक टर्नओवर और 17,000 रोजगार प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य इसे कुछ वर्षों में 12-13 अरब तक बढ़ाना है। दोनों देश भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, जिसमें आस्ट्रेलिया टेलीमेट्री ट्रैकिंग और क्रू-माड्यूल रिकवरी क्षमताओं में योगदान दे रहा है।

ई-कॉमर्स निर्यात से छोटे शहरों के कारोबारियों को मिलेगी मददः विशेषज्ञ

नई दिल्ली। विशेषज्ञों ने कहा कि ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के सरकारी उपायों से देश के छोटे शहरों के व्यापारियों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।उन्होंने कहा कि हथकरघा, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। पायोनियर इंडिया के एक अ अधिकारी ने कहा, 'ई-कॉमर्स करूर, पानीपत, जयपुर, मुरादाबाद या तिरुपुर के किसी विक्रेता को अपनी वृद्धि यात्रा के काफी शुरुआती दौर में ही विदेशी खरीदारों तक पहुंचने की गुंजाइश दे रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ग्राहकों की खोज केवल पहला कदम है और छोटे निर्यातकों को सीमा पार भुगतान के ऐसे भरोसेमंद बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है जो ऑर्डर की संख्या बढ़ने पर उनका समर्थन कर सके। उन्होंने कहा, 'यह बदलाव न केवल भारत के निर्यात के मूल्य को बदल सकता है, बल्कि यह भी तय कर सकता है कि निर्यात आधारित आर्थिक गतिविधियां कहां संचालित होंगी। पारंपरिक निर्यात मॉडल ने अक्सर स्थापित विदेशी साझेदारों, व्यापक वितरण नेटवर्क और भारी मात्रा में खेप संभालने की क्षमता वाले बड़े व्यवसायों का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स छोटे विक्रेताओं को अपेक्षाकृत कम मात्रा के ऑर्डर से शुरुआत करने की अनुमति देकर इनमें से कुछ शुरुआती बाधाओं को कम करता है।

अर्थव्यवस्था मजबूत, कमाई दमदार, फिर भी निफ्टी को किसका इंतजार

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत वृद्धि पथ पर अग्रसर है, जिसका प्रमाण वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 फीसदी की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि और कंपनियों के उत्कृष्ट तिमाही नतीजे हैं। हालांकि, यह विरोधाभासी है कि इतनी सशक्त आर्थिक बुनियाद के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क निफ्टी पिछले करीब दो सालों से किसी बड़ी और टिकाऊ तेजी के लिए संघर्ष कर रहा है। इस अवधि में बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव तो देखा गया, लेकिन एक स्पष्ट दिशा का अभाव रहा है, जिसने निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू संकेतों की मजबूती के बावजूद, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) की लगातार बिकवाली ही इस ठहराव के प्रमुख कारणों में से एक है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल हेड चंदन तापड़िया के अनुसार, भारत की उच्च जीडीपी वृद्धि और बेहतर कारपोरेट अर्निंग्स के बावजूद निफ्टी का सपाट रहना चिंताजनक है।

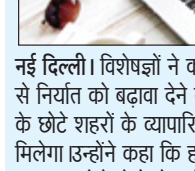

पोर्श कायेन ईवी आ रही है जल्द कीमत 1.77 करोड़ रुपये से शुरू

नई दिल्ली

लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सितंबर के अंत में पोर्श कायेन ईवी का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा।। पिछले वर्ष नवंबर में पोर्श ने इस माडल की कीमतों की घोषणा की थी। सामान्य कायेन ईवी की कीमत 1.77 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि अधिक ताकतवर टर्बो ईवी की कीमत 2.27 करोड़ रुपये है, ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। कायेन ईवी के दोनों संस्करणों में 113 किलोवाट-घंटे की बैटरी और दो मोटर वाली आल-व्हील ड्राइव प्रणाली मानक रूप से दी गई है।

टर्बो ईवी इसका सबसे ताकतवर संस्करण है, जो लान्च कंट्रोल के साथ 1,156 हार्सपावर की ताकत और 1,500 न्यूटन मीटर का अधिकतम टार्क पैदा करता है। यह महज 2.5 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रानिक रूप से 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है। कंपनी के अनुसार, इसकी डब्ल्यूएलटीपी प्रमाणित रेंज 537 किलोमीटर है। सामान्य कायेन ईवी 442 हार्सपावर की ताकत और 835 न्यूटन मीटर का टार्क देती है, और यह लान्च कंट्रोल के साथ 4.8 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम गति 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है और इसकी डब्ल्यूएलटीपी प्रमाणित रेंज 542 किलोमीटर बताई गई है। डिजाइन के मामले में, कायेन ईवी का मूल आकार इंजन वाले कायेन से मिलता-जुलता है, लेकिन इसे ईवी के अनुरूप कुछ खास बदलाव दिए गए हैं। आगे की तरफ एक बंद ग्रिल दी गई है, जबकि बंपर के दोनों किनारों पर बैटरी और इलेक्ट्रिक उपकरणों को ठंडा रखने के लिए वायु प्रवेश मार्ग दिए गए हैं। टर्बो संस्करण में ये वेंट और भी बड़े हैं। पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट पट्टी के साथ रोशन पोर्श नाम दिया गया है। केबिन में तीन तीलियों वाला स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल चालक सूचना स्क्रीन दी गई है।

मित्सुबिशी मोटर्स ने एसयूवी पजेरो को किया नए जेनरेशन अवतार में पेश

नई दिल्ली। अपनी विश्व-प्रसिद्ध आफ-रोड एसयूवी पजेरोको मित्सुबिशी मोटर्स ने नए जेनरेशन अवतार में उतारकर एक धमाकेदार वापसी की है। नई पजेरो पहले थाई मार्केट में लान्च की जाएगी, जिसके बाद फिस्कल 2026 में यह जापान और आस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पहुंचेगी, और फिर 2027 से अन्य वैश्विक देशों में उपलब्ध होगी। यह वापसी आफ-रोड उत्साही लोगों के लिए बेहद रोमांचक खबर है। 1982 में लान्च हुए इस माडल की यह पांचवीं जनरेशन है, जिसे कंपनी का नया फ्लैगशिप क्रास-कंट्री एसयूवी बनाया गया है। नई पजेरो एक मजबूत लैडर फ्रेम चेसिस, एक अत्यधिक एडवांस 4डब्ल्यूडी सिस्टम और एक प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती है, जो इसे किसी भी सड़क की स्थिति में एक भरोसेमंद और आरामदायक सफर का वादा करती है। इसके पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें एक 2.4-लीटर क्लीन डीजल इंजन है जो 150 किलोवाट की शक्ति और 480 न्यूटन-मीटर का प्रभावशाली टार्क पैदा करता है, और इसे एक नए 8-स्पीड आटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। आफ-रोड क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए, इसमें सुपर सिलेक्ट 4डब्ल्यूडी-II और एस-एडब्ल्यूसी सिस्टम के साथ-साथ सात अलग-अलग ड्राइव मोड भी दिए गए हैं, जिनमें इको, नार्मल, ग्रेवल, स्नो, मड, सैंड और राक शामिल हैं, जो विभिन्न इलाकों के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। एक्सटीरियर डिजाइन में पहली जनरेशन से प्रेरित बोल्ड प्रोपोर्शन और आधुनिक टी-शेप्ड हेडलाइट्स हैं। केबिन के अंदर, एक डुअल 14.3-इंच स्क्रीन वाला मोनोलिथिक डिस्प्ले और 7-सीटर लेआउट मिलता है। सुरक्षा के लिए इसमें आठ एयरबैग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिए गए हैं, जो इसे एक बेहतरीन और सुरक्षित पैकेज बनाते हैं। डबल-विशबोन फ्रंट और फाइव-लिंक रिजिड रियर सस्पेंशन बेहतरीन आफ-रोड क्षमता के साथ-साथ आरामदायक राइड भी प्रदान करते हैं, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 230 मिमी है।

केन्या में सभी नियामकीय नियमों का कर रहे पालन : टाटा केमिकल्स

नई दिल्ली

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारतीय दिग्गज टाटा केमिकल्स को झटका देते हुए सदी पुराने मैगाडी सोडा ऐश संयंत्र से बाहर निकलने का आदेश दिया है। इसके बाद टाटा केमिकल्स ने स्पष्ट किया है कि उसकी स्थानीय अनुषंगी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड (टीसीएमएल) सभी नियामकीय आवश्यकताओं का पालन कर रही है और सरकार को सभी जरूरी सूचनाएं व दस्तावेज जमा करा चुकी है।

टीसीएमएल को केन्या के खनन, समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री मामलों के मंत्रालय का 28 जुलाई को परिचालन निलंबित करने को लेकर पत्र मिला था। इसके बाद कंपनी ने 11 अगस्त को मांगी गई सभी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करा दिए थे। अब टाटा केमिकल्स मंत्रालय द्वारा इन दस्तावेजों की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है।

कंपनी ने नियामकीय अनुपालन का दावा किया, सभी दस्तावेज जमा किए

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि वह केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करती है और लंबित मुद्दों को उचित कानूनी एवं नियामकीय माध्यमों से सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत जारी रखने को प्रतिबद्ध है। कंपनी ने 2005 में मगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था। ष्ट्रपति रूटो ने टाटा पर आरोप लगाया कि कंपनी के पास 100 साल से खनन अधिकार हैं, लेकिन उसने काजियाडो में कुछ नहीं बनाया और संसाधन भारत तथा अन्य स्थानों पर ले जाती रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार टाटा की जगह दो नई कंपनियों को लाएगी, जिनमें से एक कांच का कारखाना और दूसरी रसायनों का उत्पादन करेगी। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी खनन मंत्रालय द्वारा टीसीएमएल को बकाया खनन शुल्क और अन्य नियामकीय कमियों का हवाला देते हुए परिचालन निलंबित करने के निर्देश के लगभग पांच सप्ताह बाद आई थी।

मोनोमार्क इंजीनियरिंग, आरकेबी ग्लोबल को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और आरकेबी ग्लोबल लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दे दी है। सेबी की ओर से दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, नियामक ने मोनोमार्क इंजीनियरिंग के प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम पर चार सितंबर को अपनी टिप्पणियां जारी कीं, जबकि आरकेबी ग्लोबल को 31 अगस्त को टिप्पणियां मिली थीं ।आईपीओ प्रक्रिया में सेबी की टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण चरण होती हैं। इसके बाद कंपनियां अपने प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए अगली प्रक्रियाओं की तैयारियां कर सकती हैं। मसौदा दस्तावेजों के अनुसार, मोनोमार्क इंजीनियरिंग के सार्वजनिक निर्गम में 2.70 करोड़ तक नए शेयर जारी किए जाएंगे और इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई हिस्सा नहीं होगा। आरकेबी ग्लोबल के आईपीओ में 1.26 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और 20.20 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। ये मंजूरियां प्राथमिक बाजार में लगातार जारी गतिविधियों के बीच मिली हैं। कई कंपनियां इस महीने सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी कर रही हैं।

डीपीए कांडला ने शिप-टू-शिप ट्रांसशिपमेंट में 12.7 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर बनाया रिकार्ड

नई दिल्ली

गुजरात के कच्छ में स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (डीपीए), कांडला ने नया कीर्तिमान रचा है। डीपीए ने शिप-टू-शिप ट्रांसशिपमेंट में 12.7 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च आंकड़ा पार कर एक नया ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया है।

दीनदयाल पोर्ट अथारिटी ने एक बयान में बताया कि यह सफलता एक सितंबर, 2026 तक के संचालन में हासिल की गई है, जो कि शिप-टू-शिप आपरेशन्स के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह इसके आपरेशनल सफर में एक और अहम उपलब्धि है।

डीपीए कांडला ने एक्स पर जारी पोस्ट में इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि बंदरगाह की बढ़ती समुद्री क्षमताओं, कुशल कामकाज और देश के लाजिस्टिक्स इकोसिस्टम को बेहतर बनाने तथा बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका को दर्शाती है।

यह उपलब्धि कांडला बंदरगाह की उच्च परिचालन दक्षता, आधुनिक समुद्री बुनियादी ढांचे और तेजी से बढ़ते व्यापारिक भरोसे को दर्शाती है। शिप-टू-शिप आपरेशंस में उल्लेखनीय वृद्धि: लाजिस्टिक्स लागत घटाने में मददगारशिप-टू-शिप (एसटीएस) ट्रांसशिपमेंट प्रक्रिया के तहत गहरे समुद्र में बड़े जहाजों (मदर वेसल्स) से छोटे जहाजों (डाटर वेसल्स) पर माल का सीधे स्थानांतरण किया जाता है।

आंकड़ों के अनुसार डीपीए कांडला पोर्ट ने 70.03एमएमटी कार्गो हैंडल किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का सबसे तेज प्रमुख पोर्ट बन गया। ये उपलब्धि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 32 दिन पहले हासिल की गई, साथ ही इसमें साल-दर-साल 23.02 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले, 27 जुलाई को डीपीए कांडला ने एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,83,816 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके एक और

रिकार्ड बनाया; इसने 17 जून को बनाए गए अपने पिछले 7,78,570 मीट्रिक टन के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया। दीनदयाल पोर्ट प्रशासन ने जारी एक बयान में कहा कि लगातार कार्गो हैंडलिंग क्षमता में विस्तार, डिजिटलाइजेशन और सुरक्षित समुद्री प्रक्रियाओं को लागू करने के चलते ये नया रिकार्ड संभव हुआ है। अधिकारियों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शेष महीनों में ट्रांसशिपमेंट के आंकड़ों में और अधिक वृद्धि की उम्मीद है, जो मैरीटाइम इंडिया विजन और बंदरगाह-आधारित आर्थिक विकास को नई मजबूती देगा।

विदेश में निवेशः अमेरिकी फंड ने दिया बंपर रिटर्न, चीन-हांगकांग में लगा झटका

नई दिल्ली

भारतीय निवेशकों के लिए विदेश में निवेश का दायरा अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है। हालांकि, अलग-अलग वैश्विक बाजारों में निवेश के कई विकल्पों के बीच, पिछले एक साल के रिटर्न ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी इक्विटी से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) ने शानदार रिटर्न दिया है, जबकि हांगकांग के कुछ टेक आधारित फंडों में निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा है।

अमेरिकी ईटीएफ से 35 फीसदी तक रिटर्न, पर हांगकांग टेक फंडों में घाटा

अमेरिकी फंडों का शानदार प्रदर्शन जारी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी बाजारों से जुड़े ईटीएफ ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ ने पिछले एक साल में करीब 35.33 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया, जो विदेशी ईटीएफ में सबसे मजबूत रहा। इसी तरह, मिराए एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ ने एक साल में करीब 30.70 फीसदी और मिराए एसेट एसएंडपी 500 टाप 50 ईटीएफ ने भी 23.54 फीसदी का मुनाफा दर्ज किया। सिर्फ एक साल नहीं, तीन साल की अवधि में भी इन अमेरिकी फंडों ने क्रमशः 31.46, 41 और 27.54 फीसदी तक का सालाना रिटर्न दिया है,

जो अमेरिकी टेक और बड़ी कंपनियों की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। हांगकांग टेक में झटका, पर हर चीनी फंड कमजोर नहीं इसके विपरीत, हांगकांग के टेक शेयरों से जुड़े कुछ फंडों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मिराए एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ ने पिछले एक साल में करीब 10.82 फीसदी का नुकसान दिया। हालांकि, चीन से जुड़े सभी फंडों की तस्वीर एक जैसी नहीं रही। निप्पान इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग बीईईएस ने इसी अवधि में 12.06 फीसदी का सकारात्मक रिटर्न दिया, जो दो और तीन साल की अवधि में क्रमशः 30.92 फीसदी और 20.59 फीसदी तक पहुंचा। यह स्पष्ट करता है कि विदेशी निवेश में सिर्फ देश का नाम देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। फंड जिस सूचकांक को ट्रैक करता है, उसमें शामिल कंपनियां और रुपये की चाल भी रिटर्न को प्रभावित करती है। निवेशकों को गहराई से विश्लेषण कर ही निवेश का निर्णय लेना चाहिए।